(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रतिबंध के कब तक हटा लिये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्री (डा. बलराम जाखड़) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से एक मण्डी हस्तक्षेप योजना को पहले ही अन्तिम रूप दे दिया है, जिसमें 1-1-92 से 29-2-92 तक की अवधि में 30,000 मीटरी टन अच्छी औसत किस्म की प्याज की खरीद 75 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जायेगी। यह खरीद केन्द्रीय नोडल एजेंसी अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और राज्य द्वारा मनोनीत एजेंसी द्वारा बराबरी के आधार पर की जायेगी। यह योजना भारत सरकार द्वारा इस शर्त पर स्वीकृत की गयी है कि राज्य सरकार पिछले वर्षों की हानियों सहित हानियों का वहन केन्द्र सरकार के साथ बराबरी के आधार पर करेगी और राज्य एजेंसी नियुक्त करेगी। राज्य सरकार ने इस योजना के मान-दण्डों के संबंध में अभी तक अपनी सहमति सूचित नहीं की है।

(घ) आयात-निर्यात नीति 1990-93 के अधीन, प्याज खुले सामान्य लाइसेंस (4) की श्रेणी में आता है और इसका निर्यात नेफेड के माध्यम से किया जाता है, जो सम्बद्ध जहाज व्यापारियों के साथ प्याज का निर्यात करते हैं। इस प्रकार, प्याज के निर्यात पर कोई रोक नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

74*[*Transferred to the 5th March,*

Food famine in Tripura

*75. DR. BAPU KALDATE :
SHRI M.S. GURUPADASWAMY :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have made any on-the-spot assessment of the food famine in the inaccessible and remote villages in Tripura leading to starvation deaths;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what measures have been taken by Government to provide relief to the affected areas to prevent starvation deaths?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR) : (a) and (b) Senior Officials of Government of Tripura have visited inaccessible and remote villages. No case of starvation death has been reported from these villages.

(c) The State Government is implementing various schemes like Jawahar Rojgar Yojana and State Rural Employment Programme in all parts of Tripura particularly covering the hilly and interior areas to generate employment to the rural poor. Adequate availability of foodgrains is also ensured in critical areas by the State Government.

उत्तर प्रदेश में यूरोपीय समुदाय द्वारा वित्त-पोषित कृषि परियोजनाएं

*76. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ऐसी कृषि परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं ; जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा सहायता प्रदान की गई है ; और

(ख) इस प्रकार की सहायता के लिए गत तीन वर्षों के दौरान जिला-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और उन्हें प्राप्त करने में कहां तक सफलता मिली है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित दो चल रही कृषि परियोजनाओं के लिए यूरोपीय